

नाबार्ड ने राजस्थान को 1,974 करोड़ रुपए की स्वीकृतप्रदान की

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2023-24 के लिये ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास नधि(RIDF) के तहत, [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक \(NABARD\)](#) ने राजस्थान सरकार को 1,974.07 करोड़ रुपए की स्वीकृतप्रदान की।

मुख्य बटु:

- नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महापरबंधक के अनुसार अजमेर, जालोर और कोटा ज़िलों में तीन ग्रामीण पेयजल आपूर्तपरियोजनाओं के लिये 930.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- राज्य के रेगसितानी और आदवासी क्षेत्रों में 676 ग्रामीण सडकों के नरिमाण के लिये 926.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये।
- इससे पहले राज्य के सभी ज़िलों में 104 पशु चकितिसालयों और 431 उपकेंद्रों के नरिमाण के लिये 117.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये थे।
- पेयजल आपूर्तपरियोजनाओं से 2,500 गाँवों के 2.87 लाख घरों को स्वच्छ और पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जबकि ग्रामीण सडक परियोजनाओं से 12 ज़िलों के 1,229 गाँवों में कनेक्टविटी में सुधार होगा।
- नाबार्ड सूक्ष्म सचिाई नधि से 740 करोड़ रुपए की सहायता से 4.28 लाख हेक्टेयर भूमिको सूक्ष्म सचिाई के अंतरगत लाने में भी राज्य सरकार का समर्थन कर रहा है।
- नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अससि्टेंस के तहत 623.38 करोड़ रुपए की सहायता के बादकोटा और बूंदी ज़िलों में 450 किलोमीटर लंबी मटिटी की नहरे नरिमाणाधीन है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रति करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वतित प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकगि संस्था है।
 - इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थति है।
- यह वर्ष 1982 में संसदीय अधनियिम-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधनियिम, 1981 के तहत स्थापति एक वैधानिक नकाय है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास नधि(RIDF)

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वतितपोषण के लिये की गई थी।
- इस नधिके रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा कया जाता है।
- नधिके मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामतिव वाले नगिर्मों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चल रही ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।